

“निर्धनता— एक पुनर्विचार”— राष्ट्रीय सेमीनार
न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोटी द्वारा समापन सभा में दिया गया वक्तव्य
(दिनांक 30.08.2008)

मध्यप्रदेश शासन और राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, विशेषकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन को, निर्धनता के सभी पक्षों पर विचार मंथन हेतु आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र में अपनी ओर से और भारतवर्ष के नागरिकों की ओर से आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने विश्व और देश की एक ज्वलंत समस्या पर विचार केन्द्रित किया है और समाधान की दिशा में एक सार्थक पहल की है। विश्व के सभी देशों के सामने समस्याएं और चुनौतियां रहती हैं किन्तु अन्तर यह होता है कि कुछ देश समाधान की दिशा में चिन्तन कर ठोस कदम उठाते हैं और कुछ केवल मूक दर्शक बने रहते हैं। निर्धनता की महामारी से जूझने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने स्वयं को प्रथम वर्ग में सम्मिलित किया है यह स्तुत्य है।

हमारे देश के संदर्भ में निर्धनता एक गंभीर चुनौती है। आकड़े कभी रोचक नहीं होते किन्तु वे सत्य से साक्षात्कार कराते हैं और हमें चेतन्य भी करते हैं। वैश्विक निर्धनता पर विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में झांकना श्रेयस्कर होगा। कुछ चौंकाने वाले तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं जो चिन्तन के लिए विवश करते हैं। संपूर्ण विश्व के निर्धन व्यक्तियों में से एक तिहाई भारतवर्ष में रहते हैं। नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्धनता की निर्धारक-रेखा सवा डॉलर अर्थात् लगभग पचपन रुपये है। इस कसौटी पर परखने पर विदित होता है कि भारतवर्ष में निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 45.60 करोड़ है जो भारत की संपूर्ण आबादी का 42 प्रतिशत है। देश की आजादी के 60 वर्ष हो चुकने पर भी क्या यह जान लेना दुःखद नहीं है कि जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन इस देश की कुल आबादी 35 करोड़ थी और आज इस देश में केवल निर्धन व्यक्तियों की संख्या 45 करोड़ से अधिक है। यदि दो डॉलर अर्थात् लगभग छियासी रुपये प्रतिदिन के मानक से निर्धन व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया जाये तो भारतवर्ष में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या लगभग 83 करोड़ अथवा संपूर्ण आबादी का 75.6 प्रतिशत है।

‘सवा डॉलर’ पर टिकने वाली निर्धनता की विभाजक रेखा से गणना की जाये तो 1981 में भारत की आबादी का 59.8 प्रतिशत निर्धन था जो प्रतिशत 1990 में घटकर 51.3 प्रतिशत पर आ गया था। 1990 से 2005 में यह अनुपात घटकर 41.6 प्रतिशत रह गया है। किन्तु इस प्रगति से प्रसन्न नहीं हुआ जा

सकता। कारण यह है कि जिस गति से निर्धन व्यक्तियों की संख्या 1981 से 1990 में कम हुई थी वह गति 1990 से 2005 के बीच घट गई है। दूसरी ओर भारत की आबादी बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यद्यपि निर्धन व्यक्तियों की संख्या में कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में कमी आई है किन्तु निर्धन व्यक्तियों की कुल संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जहां 1981 में, भारतवर्ष में कुल निर्धन व्यक्तियों की संख्या 42.10 करोड़ थी वह संख्या 2005 में बढ़कर 45.60 करोड़ हो गई है। 2003-04 में हुए एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन आबादी का अनुपात शहरी आबादी की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है।

इस निर्धनता के परिणाम गंभीर हैं।

हमारे देश की एक बड़ी आबादी केवल भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करती है। हजारों की संख्या में लोग जेलों में बंद हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बेरोज़गार हैं, बंधुआ मज़दूर हैं, अपराधी हैं, बाल अपराधी हैं, मानसिक रूप से संतप्त लोग हैं, वैश्यावृत्ति है। इन सभी की संख्या हजारों और लाखों में है। बेरोज़गार व्यक्तियों और बेसहारा-कुपोषण के शिकार-बच्चों और महिलाओं की संख्या लाखों की सीमा पार कर करोड़ों में पहुंच सकती है। ठण्ड के मौसम में जब हम लोग नरम बिस्तर में रजाई ओढ़ कर सो रहे होते हैं हजारों की संख्या में 6 से 10 वर्ष आयु के बच्चे, पीठ पर बोरी टांग कर, सड़क और घूरों पर रद्दी, प्लास्टिक और बोतलों की तलाश में निकल चुके होते हैं। देश के अनेक क्षेत्रों में सिर उठा रहे आतंकवाद के कारणों में एक प्रमुख कारण निर्धनता भी है।

क्या कारण हैं इस मानवीय आपदा के। विस्तार में न जाते हुए केवल संकेत के रूप में कहा जाए तो वे हैं:-

1. **आबादी में बेतहाशा बढ़ोतरी:** बन्द्रेड रसेल के अनुसार 'population explosion is more dangerous than hydrogen bomb'. आबादी में अनियंत्रित त्वरित वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध नैसर्गिक साधनों जैसे पानी और भोजन में कमी आ जाती है।
2. **अशिक्षा एवं अज्ञान**
3. **ग्रामीण विकास की उपेक्षा:** प्रगति हुई है; उद्योग और वाणिज्य बढ़े हैं किन्तु इस सबका लाभ शहरी क्षेत्रों को मिला है, ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित और वंचित, शहरों से कटे हैं।

4. **बेरोजगारी:** रोजगारों के जो नये अवसर उपलब्ध हुए हैं उनका वितरण तदर्थ योग्य आबादी में सामान्य रूप से नहीं हुआ है। इन अवसरों का उपयोग देश के अभिजात वर्ग (Elite Class) ने अधिक किया है।
5. **भ्रष्टाचार (Corruption):** Transparency International की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 120 देशों की उस सूची में भ्रष्टाचार विहीनता के क्रम से सूची बनाई जाये तो हमारे देश का स्थान 72वें स्थान पर आता है।

यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य है कि उक्त सभी कारण और निर्धनता—परस्पर अवलंबित हैं। उदाहरण के लिए अशिक्षा, अज्ञान, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि के कारण निर्धनता पनपती है और दूसरी ओर ये सभी सामाजिक रोगों के पनपने में निर्धनता का योगदान रहता है।

निर्धनता क्या है? विशेषज्ञों ने निर्धनता की परिभाषा अनेक आधारों अथवा दृष्टिकोणों से की है। सर्वाधिक स्वीकृत आधार आय का है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ खर्च करने की क्षमता अथवा क्रय करने की शक्ति के आधार पर निर्धनता का निराकरण करते हैं। एक विषद् दृष्टिकोण जो अधिक मानवतावादी और मानव कल्याण सापेक्ष है वह यह है कि एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे किस सीमा तक विचाराधीन व्यक्ति को उपलब्ध हैं? यह प्रश्न पूछा जाए। उदाहरण के लिए, पूछा जाए कि क्या इस व्यक्ति को न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सीमित दूरी में पीने योग्य पानी, साफ—सुथरे शौचालय उपलब्ध हैं। भोजन, वस्त्र और सिर के ऊपर छत की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाना ही निर्धनता से परित्राण नहीं है; एक कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) और स्वतंत्र देश के नागरिकों के लिए ये कसौटी मान्य होनी चाहिए कि यदि उन्हें शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, सम्मानजनक रोजगार, न्यूनतम शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवायें और उचित विश्राम नहीं मिल पाता है तो वे निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

निर्धनता की अनेक परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं। दो या तीन का उल्लेख पर्याप्त होगा।

Grolier, Encyclopedia, Deluxe Home Ed. Vol. 15, p. 478

Poverty is a lack of goods and services necessary to maintain a minimal adequate standard of living. The definition of the terms '*adequate*' varies, however, with the general standard of living in a society and with public attitudes toward deprivation.

Dr. N.R. Madhava Menon (an eminent jurist)

‘Poverty is need. It is lack of opportunity. It is a state of helplessness to cope with hostile forces and exploitative institutions. It is absence of dignity and self respect. It is vulnerability to injustice. It is a condition or relationship to society whether poor people are made to feel that equality and freedom are rights, enjoyed by privileged few only.... to be poor means not having enough income to meet basic needs of life.’

Amartya Sen

‘Poverty is deprivation of common necessities that determine the quality of life, including food, clothing, shelter and safe drinking water, and may also include the deprivation of opportunities to learn, to obtain better employment to escape poverty, and/or to enjoy the respect of fellow citizens. Among others, the economic aspects of poverty may focus on material needs, typically including the necessities of daily living, such as food, clothing, shelter, or safe drinking water. Poverty in this sense may be understood as a condition in which a person or community is lacking in the basic needs for a minimum standard of well-being and life, particularly as a result of a persistent lack of income. Analysis of social aspects of poverty links conditions of scarcity to aspects of the distribution of resources and power in a society and recognizes that poverty may be a function of the diminished "capability" of people to live the kinds of lives they value’ (Amartya Sen, 1985, *Commodities and Capabilities*, Amsterdam, New Holland, cited in Siddiqur Rahman Osmani, 2003, *Evolving Views on Poverty: Concept, Assessment, and Strategy*)

And lastly

Poverty may also be understood as an aspect of unequal social status and inequitable social relationships, experienced as social exclusion, dependency, and diminished capacity to participate, or to develop meaningful connections with other people in society.

The real cause of poverty, in the words of Amartya Sen, is the difference between ‘sympathy’ and ‘commitment’ (‘सहानुभूति’ और ‘संकल्प’ या ‘प्रतिबद्धता’). We have sympathy for the poor or the impoverished but we have no commitment for eradicating poverty. Sympathy is a lip service, showing concern for someone else’s welfare; commitment is indicative of a capacity and willingness to sacrifice. Mahatma Gandhi’s concern for poverty was a kind of commitment with which he imbued most of the nationalist movements.

I do not wish to criticize, but do wish to share my impression with you that many a social activists, NGOs and certainly the officials and planners put a full-stop to their concern by just displaying sympathy.

Dr. Upendra Baxi has minced no words in observing that 'poverty' alleviation programmes, even when they show some concern for the 'poor', are largely directed to meet the needs of party political regimes and the gap, between the rhetoric on war against 'poverty' and the reality, in terms of changing the life-conditions of the 'poor', is very often a function of coherence of political ideologies, ways of organization of party cadres, and the leadership styles.....Politics of 'poverty' and poverty of politics go together in India. Politics of 'poverty' is that process of class practices which focuses on the 'poor' as a political resource. 'Poverty' of politics refers to processes and practices where political actors fail to perceive that inherent in the 'politics of poverty' is a logic of performance which cannot, for too long, be repudiated without serious threats to the prevalent models of the organisation of distribution of political power in the Indian society. (Law and Poverty;Critical Essays, Upendra Baxi, 1988 pp. xii, xiii).

निर्धनता के उन्मूलन के लिए सकारात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता है। संकल्प चाहिए और प्रतिबद्धता भी; शासन की भी और समाज की भी।

निर्धनता समाज में व्याप्त सभी बुराईयों और अपराधों की जड़ है। जब तक देश और समाज गरीबी से अभिशप्त हैं समाज में आदर्श और नैतिकता की स्थापना नहीं हो सकती। जॉन एफ. कैनेडी ने 1961 में कहा था कि यदि एक स्वतंत्र समाज गरीबों का सहारा नहीं बन सकता तो उस समाज में मुट्ठी भर अमीर सुरक्षित नहीं रह सकते। हमें समझ लेना चाहिए कि यदि हम गरीबी के उन्मूलन के मार्ग पर नहीं चल सकते तो हम उस दिशा में चलने की तैयारी कर रहे हैं जहां या तो क्रान्ति होगी या समाज नष्ट हो जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक वार्तालाप को उद्धृत करते हुए (पुस्तक—पिगमेलियन) अपनी बात समाप्त करता हूं। गवर्नर पिकरिंग ने डूलिटिल से पूछा— 'क्या तुम्हारी कोई नैतिकता और आदर्श नहीं है?' डूलिटिल ने उत्तर दिया— 'गवर्नर महादेय, इन चीजों का भार मैं वहन नहीं कर सकता। और आप भी नहीं कर पाते यदि आप भी उतने ही गरीब होते जितना कि मैं हूं।

[John Bernard Shaw, **Pygmalion**: Governor Pickering asked Dolittle— 'Have you no morals, man?' Dolittle replied—'Cannot afford them, Governor. Neither could you, if you were as poor as me']